

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3217 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम

† 3217. श्री दुष्यंत सिंह :

श्री राजेश वर्मा :
श्रीमती शांभवी :
श्री नरेश गणपत म्हस्के :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा जनवरी, 2021 से देश में समुद्री क्षेत्र में और ज्यादा हरित और अधिक सतत विकल्पों को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) के लिए कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है;
- (ग) जीटीटीपी के अंतर्गत परिवर्तन के लिए पहचाने गए उन पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टर्गों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए अगले पांच वर्षों में हरित और अधिक सतत विकल्पों का चयन किया जाएगा;
- (घ) क्या सरकार अगले दस वर्षों में अन्य संघटकों को शामिल करने के लिए उपरोक्त कार्यक्रम का विस्तार करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) कार्बन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के संदर्भ में ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के प्रत्याशित पर्यावरणीय लाभों का ब्यौरा क्या है और इस परिवर्तन से पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करने की किस प्रकार संभावना है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने महापत्तनों में सतत विकास और विभिन्न हरित पहलों के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए महापत्तनों को एक ढांचा तंत्र प्रदान करने

के लिए हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) हेतु कोई निधियां जारी नहीं की है, क्योंकि जीटीटीपी का उद्देश्य पत्तन की स्वयं के संसाधनों का उपयोग करना है।

(ग) से (ङ): जीटीटीपी का उद्देश्य 2030 तक सभी महापत्तनों पर प्रचालनरत टग बेड़े (स्वामित्व वाले और किराए पर लिए गए दोनों) के कम से कम 30% को हरित और अधिक संधारणीय वैकल्पिक ईंधन में बदलने का है। जीटीटीपी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की परिकल्पना की गई है, जिसे 2040 तक पूरा करने की योजना है, ताकि भारत के पत्तनों में हार्बर टग बेड़े को मौजूदा डीजल ईंधन वाले टग से हरित टग में निर्बाध रूप से परिवर्तित किया जा सके। इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने, पेरिस समझौते का समर्थन करने और नौवहन क्षेत्र में निवल-शून्य जीएचजी उत्सर्जन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
